Fiscal Policy and Full Employment

I

राजकोषिय नीति का अर्थ सरकार की व्यय, कर, ऋण तथा ऋण के प्रबन्ध से सम्बन्धित उन क्रिया कलापों से है जिनका प्रयोग सरकार उत्पादन, आय, रोजगार, कीमत स्तर तथा आर्थिक विकास पर वांछित प्रभाव लाने व अवांछित प्रभावों को टालने के उद्देश्य से करती है।

Classical economists अबन्ध नीति (Laissez faire) के सिद्धान्त में विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है। अतः अर्थव्यवस्था पूर्णरोजगार की स्थिति पर स्वयमेव पहुंच जाती है अतः इसमें किसी प्रकार के राजकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।

परन्तु कीन्स तथा लर्नर जैसे आधुनिक अर्थशास्त्रीयों ने राजकोषिय नीति की प्राचीन विचारधारा को स्वीकार नहीं किया। कीन्स का मत था कि उन्नत अर्थव्यवस्था में आय बढने के साथ साथ उपभोग के प्रति रुझान कम हो जाता है और बचत की प्रवृति बढ जाती है। अधिक बचत और कम उपभोग की इस प्रवृत्ति का परिणाम यह होता है कि अर्थव्यवस्था में असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है इस संतुलन को बनाये रखने के लिए सरकार का दायित्व होता है कि वह सरकारी व्यय में वृद्धि करे। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार राजकोषीय नीति एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा सरकारी व्यय और आय में परिवर्तन कर मांग और पूर्ति के बीच सन्तुलन कायम कर पूर्ण रोजगार की स्थिति लाई जा सके।

राजकोषीय नीति के उद्देश्य

राजकोषीय नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि अर्थव्यवस्था पूर्णतया विकसित है तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य 'आर्थिक स्थिरता' प्राप्त करना होता है। यदि अल्पविकसित है तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य तीव्र रूप से आर्थिक विकास करना होता है।

किसी अल्पविकसित देश की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक संवृद्धि के लिए क्रियात्मक वित्त प्रबन्धन और उसकी व्यवस्था करना है। राजकोषीय नीति का उद्देश अल्पविकसित देशों के लिए न तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के ठोस वित्त के सिद्धान्त के अनुसार 'तटस्थ' होगा जिसमें सरकारी व्यय अनुत्पादक होते हैं और न कीन्सवादी स्फीतिक प्रकार का होगा जिसमें निवेश वृद्धि की निरंतरता का अभाव पाया जाता है और न ही हैराड-डोमर के दृष्टिकोण पर आधारित होगा जिसके अर्थव्यवस्था में विनियोग की बहुत ऊँची दर उपलब्ध होती है।

भारत जैसे अल्पविकसित देशों में राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार होते हैं -

1. रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना

To increase Employment opportunity —

भारत जैसे विकासशील देश जो गरीबी के दुश्चक्र में फंसे हुए हैं जहाँ आय, बचत तथा उपभोग का स्तर अत्यन्त ही कम है राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ सभी को रोजगार मिल सके।

एक विकासशील अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता पड़ती है। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय के दो रूप हो सकते हैं ① समुद्दीपन व्यय (Pump priming Expenditure) तथा ② क्षतिपूरक व्यय (Compensatory Expenditure)। यहाँ समुद्दीपन व्यय का अर्थ है निजी व्यय में वृद्धि करने के लिए सरकारी व्यय द्वारा नई क्रयशक्ति का सृजन करना तथा क्षतिपूरक व्यय का अर्थ है - निजी मांग की कमी को पूरा करने के लिए सरकारी बजट में किए गए व्यय में परिवर्तन। इन दोनों राजकोषीय उपायों से निवेश, आय एवं रोजगार स्तरों को ऊँचा बनाने में मदद मिलती है।

कीन्स ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निर्माण नीति (Public work Policy)

का समर्थन किया है सार्वजनिक निर्माण कार्यों से लोगों के हाथों में क्रयशक्ति पहुँचेगी जिससे उनका उपभोग व्यय बढ़ेगा, बाजार माँग में वृद्धि होगी फलतः उत्पादन एवं रोजगार बढ़ेगा तथा अर्थव्यवस्था सुस्ती व मंदी की दशाओं से मुक्त हो जायेगी। रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए केन्स ने लीफ रीकिंग (Leaf Raking) तक का सुझाव दिया। लीफ रीकिंग का अर्थ अनुत्पादक कार्यों में सार्वजनिक निवेश से है, जैसे गड्ढे खुदवाना और उन्हें पुनः मिट्टी से भरवाना आदि। इसी तरह सरकार राजकोषीय नीति के अन्य उपकरणों अथवा अस्त्रों जैसे - करारोपण की नीति, सार्वजनिक ऋण नीति आदि के माध्यम से भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि ला सकती है।

2. आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना (To increase Economic Growth Rate)

विकासशील देशों की प्रमुख समस्या होती है देश का तेजी के साथ विकास करना। इसकी पूर्ति के लिए राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक संवृद्धि दर को बढ़ाना है।

सरकार को करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था आदि राजकोषीय उपायों का प्रयोग ऐसे तालमेल के साथ करना चाहिए ताकि उत्पादन, उपभोग तथा वितरण पर इनका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े बल्कि सम्पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था का इस तरह विकास हो कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि हो सके। इससे आर्थिक विकास की दर जनसंख्या वृद्धि दर से आगे निकल सके। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह विद्युत व शक्ति के साधनों तथा सड़क, परिवहन एवं संचार सुविधाएँ सम्बन्धी उद्योगों को बढ़ावा दे। निजी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश को प्रेरित करे। कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों में उत्पादन की नई-नई एवं आधुनिक विधियों की खोज हेतु सुविधाएं, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण